

आज अत्यन्त कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति को यदि तत्काल नियन्त्रित नहीं किया गया तो बहुत बड़ी संख्या में हथकरघा उद्योग में लगे हुए लोगों को बेरोजगारी और भुखमरी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सूत और कौमिकल के वर्तमान मूल्यों को कम करे एवं उसकी आवश्यकता सरकारी मेल्ल डिपों से की जाये। बुनकरों को बैंक से आसान शर्तों पर आश्चर्यकृतानुसार कर्ज दिया जाए, जिस पर व्याज को दर कम हो और बुनकरों से संबंधित सरकारी विभागों में बेरोजगार शिक्षित बुनकरों को सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में तत्काल प्रभावी कदम उठाए जिस से बुनकरों की समस्याओं का समाधान हो सके।

(vi) ALLEGED POLLUTION OF THE DAMODAR RIVER WATER

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के छोटा नागपुर से होता बंगाल तक जाने वाली प्रमुख नदी दामोदर नदी है। बिहार के विद्युत परिषद् के पतंगानुधर्मस पावर स्टेशन तथा केन्द्र सरकार ऊर्जा मंत्रालय के सेंट्रल कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा अपनी वाशरी के गंदे पानी को नदी में बहाकर दामोदर नदी के पाने के पानी को दूषित किया जा रहा है। अभी छोटा नागपुर में पांच वाशरी हैं गिददी, स्वांग, करगली, दुगरा और चन्द्रपुरा। इस जल प्रदूषण से सैकड़ों मील में बसे हरिजन आदि-वासी तथा अत्यन्त पिछड़े और गरीब लोग पीलिया रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। लीवर तथा अन्य दूसरी बीमारियों का शिकार हो कर भर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह पानी है, जिस को मैं रोकूंगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please read.

श्री राम विलास पासवान : जातधरों ने भी भय के मारे इस दूषित पानी को पीना बंद कर दिया है। एक तो ऐसे ही छोटा नागपुर में स्वच्छ पेय जल का अभाव है दूसरे दामोदर का जल, जो गरीबों के लिए प्राण है, वह भी जहर के समान हो गया है। लाखों जन संख्या इस से प्रभावित हैं।

देश में जल प्रदूषण कानून के उपबंधों के अधीन किसी को भी नदियों का या अन्य स्रोतों का जल प्रदूषित करने का अधिकार नहीं है, परन्तु बिहार सरकार एवं केन्द्र सरकार इसे उल्लंघन कर पानी को दूषित कर गरीबों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है।

अतः सरकार लाखों गरीबों की जीवन रक्षा हेतु जल को और अधिक प्रदूषण होने से बचाए। इस जल प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस कार्यवाही करे।

मैं आप की आज्ञा से इसे रख देता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may give it to the Minister.

(vii) ALLEGED ANNEXATION OF GOLAN HEIGHTS BY ISRAEL

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, गोलान हाइट्स को जबरदस्ती हजम कर के इजरायल ने अपने आक्रमणात्मक स्वैये का एक और प्रमाण दिया है। इजरायल का यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की गहरी अवमानना तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।

[श्री प्रद्युम्न सिंहारी वज्रयोगी]

इजरायल के इतना आदर से पश्चिम एशिया में फिर से युद्ध की आशंका भड़क सकती है। 1973 के युद्ध के बाद जो युद्ध निराम समझौता हुआ था उसका इजरायल खुला उल्लंघन करने का दोषी है।

भारत सरकार को इजरायल के इस दृष्टि को बड़ी निन्दा करने चाहिए और विश्वमन को इजरायल के विरुद्ध संयुक्त कदम के उभे गोलाबत हाइड्रस पर सौरिया के प्रभुत्व को स्वीकारने के लिए विवश करना चाहिए।

(viii) NEED TO CHECK PRICE OF RAW SILK YARN IN TAMIL NADU

*SHRI C. PALANIAPPAN (Salem): Under Rule 377 I wish to raise the following matter of urgent public importance. Due to acute shortage of silk yarn, the silk weaving industry in Tamil Nadu is on the verge of extinction, resulting in the loss of livelihood to thousands of silk weavers in the State. In Tamil Nadu, weaving is the traditional industry in which 5.5 lakhs of people are engaged and their dependents number about 7.5 lakhs of families. One lakh families are dependent on silk weaving industry. In Salem district alone, 7000 looms are there both within the city and in the surrounding rural areas. In 1980 the raw silk yarn known as KORAPATTU was Rs. 250 per bundle and Rs. 415 per bundle of BLANCHER YARN. In November 1981 the price of both types of raw silk yarn has gone to Rs. 525 and Rs. 640 respectively. The spiralling price of Korapattu yarn during the past 6 months affected most of the weavers in the State. Unless the price of this silk yarn is controlled there will be

no redemption for the weavers. The Silk Board of Karnataka and the exchange organisation located in Bangalore are primarily responsible for this steep rise in the price of silk yarn. In the auctions conducted by this Exchange Organisation the prices are artificially hiked by wholesalers with whom the traders cannot compete. The Silk Board is compelled to pay that price and consequently the price of silk also goes up. There is urgent necessity for controlling the price of raw silk yarn. In order to bring down the price of coconut oil, the Government resorted to the import of copras. Similarly in order to bring down the price of Korapattu, the Government should import a minimum quantity of 5 lakhs to 7 lakhs of Korapattu and it must be distributed among the weavers. Then only the price will come down and the lakhs of weavers engaged in silk weaving will be given succour by the Government of India by taking this step.

12.40 hrs.

DEMANDS** FOR EXCESS GRANTS (GENERAL), 1979-80 AND SUPPLEMENTARY DEMANDS AND FOR GRANTS (GENERAL), 1981-82

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up discussion and voting on the Demands for Excess Grants (General) and Supplementary Demands for Grants (General). Both the items No. 11 and 12 will be taken up together for which four hours have been allotted. Now it is 12.40 p.m. We will have to complete the discussion after the expiry of four hours. Therefore, I request the hon. Members not to take more time. If they take more time the other hon. Members either from Opposition or the Ruling party may not have the chance to speak. Therefore, they should not blame me.

*The original speech was delivered in Tamil.

**Moved with the recommendation of the President.